भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 639
उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2022

मोबाइल टावरों का लगाया जाना

639. श्री सौमित्र खान:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खराब कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) महामारी के वर्षों के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के कारण इंटरनेट की खपत में भारी वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाओं से सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कब तक जोड़ा जाएगा?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) महोदय, सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के माध्यम से चरणबद्ध रूप में उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने देश भर के ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड कवरेज उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ के माध्यम से विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। उन स्कीमों का ब्यौरा **अनुलग्नक** पर दी गई है।

(ख)से (घ) सरकार ने दिनांक 23.10.2019 को बीएसएनएल के लिए पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को शामिल किया है। अखिल भारत स्तर पर 4जी सेवाओं के शुभारंभ के साथ पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बीएसएनएल वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार होगा।

उपरोक्त के अलावा बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) सेवाएं उपलब्ध कराता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) सेवाओं के विस्तार सहित विभिन्न पहल की है। पश्चिम बंगाल सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एफटीटीएच कनेक्शनों के प्रावधान के संवर्धन हेतु भारतनेट का प्रचालन और रखरखाव बीएसएनएल को दिया गया है। बीएसएनएल ने अपने इन प्रयासों से वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 (30.06.2022 तक) की अवधि के दौरान 71.65 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 22,10,644 एफटीटीएच कनेक्शन जोड़े हैं।

****

अनुलग्नक

देश भर के ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने/ सुविधा देने हेतु स्कीमों/परियोजनाओं का ब्यौरा:

i. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई चरण-I) स्कीम के चरण-I के तहत एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में 2,343 मोबाइल टावरों को स्थापित किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के 96 मोबाइल टावर शामिल हैं और वे सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एलडब्ल्यूई चरण-II स्कीम के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एलडब्ल्यूई राज्यों में चिन्हित स्थानों पर 2,524 मोबाइल टावरों की स्वीकृति दी गई है जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के 33 स्थान शामिल है;

ii. लद्दाख और कारगिल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उतराखंड सहित कवर न किए गए सीमावर्ती क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल राज्य के एक (1) गांव सहित अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए स्कीम;

iii. कवर न किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना;

iv. चार राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों में कवर न किए गए 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए स्कीम;

v. 5 राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों में कवर न किए गए 7287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए स्कीम;

vi. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चैन्नई तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना;

vii. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कवर न किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 223) को कवर करने हेतु मोबाइल कनेक्टिविटी;

viii. लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 10 मोबाइल टावरों की स्थापना से मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है;

ix. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 4जीबीपीएस तक सैटेलाइट बैंडविद्थ संवर्धन;

x. लक्षद्वीप समूह के लिए 1.71 जीबीपीएस तक सैटेलाइट बैंडविद्थ संवर्धन।

******